

लघु एवं सीमान्त किसानों पर किसान क्रेडिट कार्ड का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन (जनपद अलीगढ़ के विशेष संदर्भ में)

रामबीर सिंह,
असिस्टेंट प्रोफेसर
(शोध छात्र)

मान्यवर कांशीराम राजकीय
महाविद्यालय गभाना, अलीगढ़।

डॉ० (श्रीमती) बीना उपाध्याय
एसोसिएट प्रोफेसर
(शोध पर्यवेक्षक)

श्री वार्ष्णेय कॉलेज, अलीगढ़।
राजा महेन्द्रप्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

ABSTRACT

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का उद्देश्य किसानों को समयवद्ध और त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत की मौद्रिक नीति में साहूकारों (असंगठित स्रोतों) की जगह संगठित स्रोतों का उपयोग और ब्याज दरों में कमी शामिल रही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएँ ही संस्थागत ऋण का एकमात्र स्रोत रहीं हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद अनुसूचित वाणिज्य बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी औपचारिक ऋण प्रणाली का हिस्सा बन गये हैं। कृषि उत्पादकता और किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ समय-समय पर लागू की जाती रहीं हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है, जिसे 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड (NABARD) द्वारा शुरू किया गया था। प्रस्तुत अध्ययन (किसानों पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करना है, जिसके लिये अलीगढ़ जनपद के दो विकास खण्डों (खैर तथा चंडौस) का चयन किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का महत्व:

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिये समय पर ऋण उपलब्ध कराना है। यह योजना किसानों को खेती के विभिन्न चरणों में आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह किसानों, औपचारिक ऋणदाताओं और साहूकारों की जकड़ से मुक्त करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर किसान उच्च ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋणदाताओं से ऋण लेते हैं, जिससे ऋण के जाल में फंस जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ऋण मिलता है। जोकि न केवल सुरक्षित है बल्कि ब्याज दरें भी अपेक्षाकृत कम होती हैं। इससे किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और वे अपने कृषि कार्यों पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त KCC योजना के समय-समय पर किये गये सुधारों में इसके महत्व को और बढ़ाया है। वर्ष 2004 में पशुपालन और मछलीपालन को शामिल करने से लेकर 2018 में बागवानी और अन्य गैर-फसली गतिविधियों के लिये ऋण सुविधा प्रदान करने तक इन सुधारों में योजना को अधिक समावेशी और व्यापक बनाया है। डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार भी KCC योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिससे ऋण प्रक्रियाओं में तेजी और सरलता आयी है। इन सुधारों ने किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। और भारतीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान दिया है।

योजना के प्रारंभिक चरण में KCC केवल फसल ऋण के लिये उपलब्ध था किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के अनुसार ऋण की एक निश्चित सीमा दी जाती थी। जिसे वे अपनी फसल की अवधि दौरान उपयोग कर सकते हैं। इस ऋण का उपयोग बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि आगतों के लिए किया जा सकता था। योजना का मुख्य लाभ यह था कि किसान अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवश्यकता अनुसार ऋण राशि का उपयोग कर सकते थे और उन्हें ब्याज केवल उपयोग की गई राशि पर ही देना होता था।

समय के साथ KCC योजना में कई महत्वपूर्ण सुधार और विस्तार किये गये। 2004 में, पशुपालन और मछली पालन को योजना में शामिल किया गया जिससे किसानों को विभिन्न कृषि सम्बंध गतिविधियों के लिये भी ऋण मिलना शुरू हुआ। यह कदम किसानों की आय के स्रोतों में

विविधता लाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिये महत्वपूर्ण था। इसके बाद 2012 में डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं को योजना में जोड़ा गया, जिससे किसानों की एटीएम कार्ड और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ मिला। इससे ऋण प्रक्रिया में और भी अधिक तेजी और सरलता आई।

वर्ष 2018 में केसीसी योजना में बागवानी और गैर-फसली गतिविधियों के लिये भी ऋण की सुविधा प्रदान की गयी। इस विस्तार ने योजना को और अधिक समावेशी बनाया और किसानों को उनकी विविध कृषि गतिविधियों के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की। इन सभी ने **KCC** योजना की पहुँच और प्रभावशीलता को बताया है, जिससे अधिक से अधिक किसान योजना लाभ उठा सकें। इन सभी सुधारों और विस्तारों के बावजूद योजना के समक्ष कुछ चुनौतियाँ बनी हुयी हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और ऋण प्रक्रिया का जटिल होना। वर्ष 1998 से लेकर अब तक **KCC** योजना में कई सुधार किये गये हैं। शुरुआती चरण में योजना केवल फसल ऋण के लिए थी। लेकिन समय के साथ इसमें अन्य कृषि और सम्बंधित गतिविधियों के लिये भी ऋण की सुविधा जोड़ी गयी है।

किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति

तालिका-1: निर्गत किये गये कुल किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष	व्यासायिक बैंक (000)	RRBS(000)	Cooperative (000)	Total
1998-1999	6	4	12	22
1999-2000	13	17	26	56
2000-2001	39	48	61	148
2001-2002	30	7	55	22
2002-2003	27	6	48	81
2003-2004	30	12	49	91
2004-2005	44	17	36	97
2005-2006	41	12	26	79
2006-2007	48	14	30	32
2007-2008	46	18	24	88
2008-2009	58	14	15	87
2009-2010	53	20	17	90
2010-2011	55	17	28	100
2011-2012	68	20	29	117
2012-2013	82	21	29	132
2013-2014	85	22	32	139
2014-2015	83	15	36	134
2015-2016	84	22	15	171
2016-2017	233	122	358	714
2017-2018	235	121	350	692
2018-2019	236	122	304	663
2019-2020	241	122	289	652
2020-2021	307	129	301	737
2021-2022	269	135	311	715
2022-2023	283	139	314	735
2023-2024	298	145	323	772

स्रोत/ गुप्ता एट ऑल 2025

तालिका 1 में वित्तीय वर्ष 1998 से 2023 तक प्रत्येक वर्ष जारी किये केसीसी कार्डों की संख्या 1998 में लगभग 22,000 कार्डों से बढ़कर 2023 में 7.72 करोड़ कार्ड हो गयी है। जिसकी संयुक्त वार्षिक वृद्धिदर 12.51 प्रतिशत है। यद्यपि पिछले 10 वर्षों में वृद्धिदर 18.09 प्रतिशत रही है। वहीं 5 वर्षों में मध्यम रही जो 3.41 प्रतिशत रही तथा द्वितीयक आँकड़े दर्शाते हैं कि केसीसी योजना की शुरुआत से ही वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है और सहकारी समितियों की हिस्सेदारी घट रही है। वित्तीय वर्ष 2016 में हिस्सेदारी में अचानक उछाल आया जिसका कारण नीतियों में परिवर्तन डिजिटलीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण कवरेज पर नये सिरे से ध्यान केन्द्रित करना बताया गया है।

साहित्य पुनरावलोकन (Rerview of Literatura)

शर्मा, आर (2016), इस अध्ययन में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि KCC योजना ने किसानों को त्वरित और सख्ती तथा सुविधा प्रदान की है, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता और वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये कुछ सुधार आवश्यक है।

सिंह, ए. (2018); इस शोध में KCC योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार का अध्ययन किया है। इन्होंने पाया कि डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं जैसे एटीएम कार्ड और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किसानों की ऋण प्रक्रिया में सरलता और त्वरितता मिली है। इसने किसानों की बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को बढ़ाया है और उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ाया दिया है।

वर्मा, पी. (2020), वर्मा के अध्ययन के तहत KCC योजना के तहत ऋण वितरण के पैटर्न का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशि में समय के साथ वृद्धि हुयी है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता की कमी है। इन्होंने सुझाव दिया कि सरकार बैंकिंग संस्थानों को जागरूकता बढ़ाने के लिये विशेष अभियान चलाने चाहिए।

गुप्ता, एस. (2021), गुप्ता में KCC योजना के विभिन्न सुधारों और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि 2004, 2012 और 2018 में किये गये सुधारों ने योजना की प्रभावशीलता

को बढ़ाया है और किसानों की विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिये ऋण की सुविधा प्रदान की है, उन्होंने पाया कि योजना में और सुधार की गुंजाइश है ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।

मेहता, आर. (2023), इस हालिया अध्ययन में KCC योजना की वर्तमान स्थिति और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया। मेहता ने पाया कि योजना के तहत किसानों को त्वरित ऋण सुविधा मिल रही है, लेकिन ऋण प्रक्रिया की जटिलता और जागरूकता की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इन्होंने सुझाव दिया कि योजना की प्रक्रिया को और सरल तथा त्वरित बनाने के लिये डिजिटल तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

कई मॉडल और सिद्धांत KCC योजना की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने लिये उपयोग किये गये हैं। इन सिद्धांतों में कृषिवित्त, बैंकिंग सुधार और विकास अर्थशास्त्र शामिल हैं।

अध्ययन उद्देश्य (Objective Of The Study)

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करना।
2. किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए ऋण का प्रयोग कृषि कार्य हेतु हो रहा है या नहीं, इसका अध्ययन करना।
3. किसान क्रेडिट कार्ड की साख प्राविधियों से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है या नहीं का तुलनात्मक अध्ययन करना।

कार्य प्रणाली (Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन का पालन किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों के लिए सरकारी रिपोर्ट, शोध पत्र और अन्य सम्बंधित साहित्य शामिल है, जबकि प्राथमिक आँकड़ों के लिए जनपद अलीगढ़ के दो विकासखण्डों (खैर एवं चंडौस) का चयन किया गया है, और प्रत्येक विकास खण्ड से 100-100 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 200 सीमान्त तथा लघु किसानों का चयन किया गया है।

अध्ययन की आवश्यकता (Need of the study)

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समुदाय में विकासरत कृषको की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के योगदान की ज्ञात करने की जिज्ञासा इस अध्ययन के लिये महत्वपूर्ण कारक रही है।

स्वतंत्रता प्राप्ति कि पश्चात प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्तमान में किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिये विशेषकर उनकी वित्तीय सम्बंधी समस्याओं का निराकरण हेतु कई कई विकासोन्मुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, उनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (RBI) और नाबार्ड के संयुक्त सहयोग से सन् 1998-99 में शुरू की गयी थी। समय-समय पर विभिन्न शोधार्थियों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शोध कार्य हो चुके हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जनपद के संदर्भ में शोध अपेक्षित हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना द्वारा किसानों के जीवन में आये परिवर्तन एवं उनकी आर्थिक समस्या के समाधान में यह योजना कितनी मददगार हुयी है, इससे सम्बंधित अध्ययन की कमी एवं रिक्तता रही है इस कमी को दूर करने हेतु यह अध्ययन प्रस्तावित है।

प्रस्तुत अध्ययन इस दृष्टि से भी प्रासंगिक है कि यह अध्ययन ऐसे अनछुए पहलुओं की ओर भी अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित करेगा जिसपर अन्य अध्ययनों में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इस दृष्टि से इस अध्ययन का औचित्य जमीनी स्तर की आनुभाविक जानकारी उपलब्ध कराना भी है। जिसके माध्यम से यह ज्ञात हो सके कि सरकार द्वारा लागू की गयी योजनायें व्यावहारिक रूप से कितनी उपयोगी होती है।

उत्तरदाताओं का सामाजिक-आर्थिक वितरण

प्रस्तुत अध्ययन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना लघु एवं सीमान्त किसानों पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव का अध्ययन है, जिसमे अलीगढ़ जनपद के चयनित दो विकास खण्डों (खैर तथा चंडौस) का अध्ययन किया गया है, जिसमें दोनो विकास खण्डों को मिलाकर कुल 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

तालिका-2: उत्तरदाताओं का लिंगवार विवरण

क्रम	लिंगवार विवरण	चयनित विकास खण्ड				कुल योग	
		खैर		चंडौस			
1	पुरुष	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
		87	87.00	91	91.00	178	89.00
2	महिला	13	13.00	9	9.00	22	11.00
	कुल योग	100	100.00	100	100.00	200	100

जनपद अलीगढ़ में चयनित विकास खण्डों (खैर तथा चंडौस) में किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कुल दो सौ (200) हितग्राहियों में 178 (89.0 प्रतिशत) पुरुष तथा 22 (11-0 प्रतिशत) महिला लाभार्थी हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आँकड़ों यह प्रदर्शित करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के वितरण में लिंगवार विषमता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को वितरण में पुरुष की संख्या सर्वाधिक है, जबकि महिला कार्ड धारकों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित 33 प्रतिशत मानको से भी कम है।

तालिका-3: उत्तरदाताओं का वर्गवार विवरण

क्रम	वर्गवार विवरण	चयनित विकास खण्ड				कुल योग	
		खैर		चंडौस			
1	अनुसूचित जाति	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
		13	13.00	91	91.00	178	89.00
2	अनुसूचित जनजाति	—	—	—	—	—	—
3	अन्य पिछड़ावर्ग	48	48.00	43	43.00	91	45.5
4	सामान्य	28	28.00	32	32.00	60	30.5
5	अल्पसंख्यक	11	11.00	14	14.00	25	125.5
	कुल योग	100	100.00	100	100.00	200	100

प्रस्तुत तालिका में किसान क्रेडिट कार्ड के हितग्राहियों का वर्गवार विवरण प्रदर्शित किया गया है, उत्तरदाताओं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य एवं अल्पसंख्यक में विभाजित किया गया है। कुल (200) उत्तरदाताओं में से 91 (45.5 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग, 60 (30.0 प्रतिशत) सामान्य वर्ग से तथा 25 (12.5 प्रतिशत) अल्पसंख्यक वर्ग से है। जनपद अलीगढ़ से प्राप्त आंकड़े योजना के लाभार्थियों में जातिवार विषमता प्रदर्शित करते हैं। सर्वाधिक कार्डधारक अन्य पिछड़ा वर्ग है जबकि न्यूनतम अनुसूचित जाति से सम्बंधित है।

तालिका-4: उत्तरदाताओं कृषि भूमि का विवरण

क्रम	कृषि भूमि का आकार (हे.)	चयनित विकास खण्ड				कुल योग	
		खैर		चंडौस			
1	0—1	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
		18	18.00	14	14.00	32	16.00
2	2—3	61	61.00	67	67.00	128	64.00
3	4—5	13	13.00	12	12.00	25	12.5
4	5 से अधिक	8	8.00	7	7.00	15	7.5
	कुल योग	100	100.00	100	100.00	200	100

उपर्युक्त तालिका में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाभार्थी किसानों के कृषि भूमि का आकार को प्रदर्शित करता है। लाभार्थी किसानों में 0-1 हेक्टेयर भूमि वाले 32 (16.0 प्रतिशत) 2-3 हेक्टेयर भूमि वाले 128 (64.0 प्रतिशत), 4-5 हेक्टेयर भूमि वाले 25 (12.5 प्रतिशत) तथा 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले 15 (7.5 प्रतिशत) हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करती हैं कि सर्वाधिक लाभार्थी किसान 2-3 हेक्टेयर भूमि धारक है, जिन्हें सीमान्त कृषक भी कहा जाता है—न्यूनतम 5 हेक्टर भार अधिक भूमि वाले 15 (7.5 प्रतिशत) किसान हैं। किसानों के जाते ही के आधार पर विषमता प्रदर्शित करते हैं।

तालिका-5 उत्तरदाताओं का शैक्षिक विवरण

क्रम	शिक्षा का स्तर	चयनित विकास खण्ड				कुल योग	
		खैर		चंडौस			
1	निरक्षर	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
		13	13.00	91	91.00	178	89.00
2	प्राथमिक स्तर	—	—	—	—	—	—
3	जूनियर स्तर	48	48.00	43	43.00	91	45.5
4	माध्यमिक स्तर	28	28.00	32	32.00	60	30.5
5	स्नातक स्तर	11	11.00	14	14.00	25	125.5
6	परास्नातक स्तर	66	06.00	05	5.00	11	5.5
	कुल योग	100	100.00	100	100.00	200	100

(क्षेत्रीय सर्वेक्षण-2024-2025)

उपर्युक्त तालिका में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी किसानों में निरक्षर 10 (5-0 प्रतिशत), प्राथमिक स्तर 20 (10.0 प्रतिशत) जूनियर स्तर 33 (16.5 प्रतिशत), माध्यमिक स्तर 86 (43.0 प्रतिशत), स्नातक स्तर 40 (20 प्रतिशत) तथा 11 (5.5 प्रतिशत), परास्नातक स्तर की है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े उत्तरदाताओं के शैक्षिक विवरण में विषमता का प्रदर्शित करते हैं।

केसीसी योजना के बारे में जागरूकता :

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को योजना के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। किसानों में केसीसी योजना के प्रति जागरूकता की कमी पर्याप्त राशि वितरण में प्रमुख बाधा है। केसीसी योजना 1998 से पूरे भारत में संचालित हो रही है। तालिका-6 में केसीसी धारक किसानों से केसीसी जागरूकता से सम्बंधित प्रश्न पूछा गया, जिससे केसीसी के बारे में उनके ज्ञान का निर्धारण किया जा सकें।

तालिका-6: केसीसी के बारे में जागरूकता

विवरण	हाँ (प्रतिशत)	नहीं (प्रतिशत)
केसीसी अवधि	30	70
ब्याजदार	35	65
भुगतान अवधि	42	58
ऋण सीमा	48	52
प्रसंस्करण शुल्क	22	78
बचत पर ब्याज	32	68
दुर्घटना बीमा	38	62
फसल बीमा	52	48

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण, 2024-25

उपर्युक्त तालिका में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित किसानों क्रेडिट कार्ड योजना लाभार्थी किसानों की जागरूकता का अध्ययन किया गया है। जिसमें यह पाया गया है कि लगभग 70 प्रतिशत कृषक केसीसी अवधि के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ब्याज दर के बारे में 65.0 प्रतिशत नहीं जानते हैं, भुगतान अवधि के बारे में 58.0 प्रतिशत नहीं जानते हैं, ऋण सीमा के बारे में 52.0 प्रतिशत नहीं जानते, प्रसंस्करण शुल्क के बारे में 78.0 प्रतिशत नहीं जानते हैं, बचत पर ब्याज के बारे में 68.0 प्रतिशत, दुर्घटना बीमा के बारे में 62.0 प्रतिशत तथा फसल सीमा के बारे में 48.0 प्रतिशत किसान नहीं जानते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि केसीसी योजना के बारे में किसानों के मध्य व्यापक जागरूकता का अभाव पाया गया है।

1. क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़े दर्शाते हैं कि किसानों के विभिन्न वर्गों में क्रेडिट कार्ड के उपयोग का पैटर्न अलग-अलग था। क्रेडिट कार्ड का उपयोग भूमि के आकार से सकारात्मक रूप से सम्बंधित या भूमिहीन परिवारों (सीमान्त एवं लघु किसानों) में क्रेडिट कार्ड धारकों का प्रतिशत कम था जबकि बड़े कृषि परिवारों में यह प्रतिशत अधिक था।
2. क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी से यह तथ्य पता चलता है कि कम समय में क्रेडिट कार्ड की उच्च लोकप्रियता के बावजूद ग्रामीण परिवार केवल ब्याज दर के कारण ही ऋण लेने से नहीं कतराते बल्कि अन्य योजनाओं की औपचारिकता से भी कतराते हैं।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित किया क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें किसानों की अशिक्षा निकासी के लिये बैंक में अत्यधिक भीड़ और निकासी के लिये उचित प्रबंधन का अभाव शामिल है।

सामाजिक व्यवस्था में बदलाव

सामाजिक व्यवस्था में बदलाव से आशय समाज की आर्थिक सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक मौलिक तकनीकी परिवर्तन से है। योजना के प्रारम्भ होने के पश्चात् सिंचाई, यातायात शिक्षा संचार, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान मनोरंजन आदि में काफी बदलाव आया है।

पूर्व में दुर्भाग्यवश जिले में कृषि अत्यंत पिछड़ी दशा में थी, क्योंकि किसान साहूकार, महाजन, पूंजीपतियों आदि असंगठित क्षेत्र के स्रोतों से ऋण लेकर कृषि कार्य करता था, जिससे एक ओर तो लागत बढ़ जाती थी, वहीं दूसरी ओर वह ऋण जाल में फँस जाता था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से संचालित किसी योजना द्वारा किसानों को अल्पकालीन ऋण आसानी से उपलब्ध होने के कारण कृषकों के जीवन में आर्थिक सुधार हुआ है। क्योंकि योजना लागू होने के कारण उन्हें समय पर बीज, खाद, दवाईयाँ आदि आसानी से प्राप्त हो जाती है। जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुयी है। वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। कृषकों के जीवन की आर्थिक सामाजिक समस्याओं को दूर करके उन्हें प्रगति के रास्ते पर ले जाते हुए ग्रामीण व्यवस्था को संगठित और व्यवस्थित करना ही सामाजिक व्यवस्था में सुधार है, जिसके फलस्वरूप कृषकों के सभी पहलूओं का संतुलित विकास हो रहा है और उन्हें सुखी जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त रहा है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर निम्नलिखित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में बदलाव पाया गया।

1. कृषक ऋण लेने के पश्चात् वैज्ञानिक प्राद्यौगिकी के प्रयोग से अधिक अन्न उत्पादन करने लगे हैं। परिणामस्वरूप उनकी आय में वृद्धि हुयी एवं कृषि के अलावा अन्य उद्योग धन्धे करने लगे और उनके जीवन स्तर में उन्नति देखने को मिली।
2. किसानों द्वारा नये वैज्ञानिक उपकरण, उत्तम बीज, रासायनिक खाद, ट्रैक्टर थ्रेशर, पानी निकलने के यंत्र जैसे विद्युत पंप एवं डीजल पंप आदि खरीद कर खेती करने लगे हैं।
3. कृषकों की आय में वृद्धि होने से उनके जीवन में भी परिवर्तन हो रहे हैं। अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, अच्छा भोजन करने लगे हैं। ग्रामीणों कि, रहन-सहन में बदलाव आया है। मनोरंजन

के साधनों में भी परिवर्तन देखने को मिला है। कृषकों के घर में रेडियो टेलीविजन, टेप, स्पीकर, साईकिल, पंखे स्कूटर, कपड़े, घड़ी, खेल, कुर्सी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल आदि वस्तुओं दिखाई दी।

4. ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार बढ़ता जा रहा है। स्त्री शिक्षा और बच्चों की शिक्षा पर ग्रामीण कृषक अधिक ध्यान देने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इससे कृषकों की विचारधारा मनोवृत्ति और दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है। कृषकों को आधुनिक कृषि करने के लिए प्रशिक्षण एवं शिक्षा दी जा रही है, सरकार द्वारा कृषकों के लिए फ्री किसान कॉल सेन्टर खोले हैं, जिसके द्वारा कृषक अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित किसान क्रेडिट योजना के आरम्भ होने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था में सम्पूर्ण परिवर्तन हो गया है। कृषकों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उनकी आय में वृद्धि के साथ उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया है।

खोज और सुझाव (Findings and Suggestions)

1. KCC योजना ने किसानों को त्वरित और सस्ती ऋण सुविधा प्रदान की है।
2. समय-समय पर किए गए सुधारों ने योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया है।
3. योजना के समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे जागरूकता की कमी और प्रक्रिया की जटिलता।

कृषि और बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुझाव:

1. KCC योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
2. ऋण प्रक्रिया को और सरल और त्वरित बनाने के लिए डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
3. किसानों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजना में और सुधार किए जाएं।

संदर्भ (References)

- 1- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI). (2020). किसान क्रेडिट कार्ड योजना- <https://www.rbi.org.in>
- 2- नाबार्ड (NABARD). (2019). कृषि वित्त और किसान क्रेडिट कार्ड योजना. <https://www.nabard.org>
3. कुमार, एस. (2018). भारतीय कृषि में वित्तीय सुधार कृषि विकास जर्नल, 25(3), 45–60.
4. शर्मा, आर. (2016). किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रभाव. बैंकिंग रिसर्च जर्नल, 14(2), 123–138.
- 5- Singh, A- (2018) Expansion of Digital Banking Facilities under the Kisan Credit Card Scheme- Journal of Agricultural Economics, 27(3), 112-128
- 6- Verma, P- (2020) Analysis of Loan Distribution Patterns under the Kisan Credit Card Scheme- Indian Journal of Rural Studies, 32(1), 45-59.
- 7- Gupta, S- (2021) Impact of Reforms in the Kisan Credit Card Scheme- Journal of Financial Development, 36 (4), 78-94
- 8- Mehta, R- (2023) Current Status and Challenges of the Kisan Credit Card Scheme- Journal of Agricultural Finance, 40(2), 155-172
- 9- गोस्वामी, पी. (2015). कृषि क्षेत्र में वित्तीय सुधार: एक विश्लेषण. विकास अध्ययन जर्नल, 30(4), 89–102.
- 10- भारतीय कृषि मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट्स (2012–2022)